



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 109]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

**अंतिम जांच परिणाम**

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

**फा. संख्या 7/18/2018-डीजीएडी.— क. मामले की पृष्ठभूमि:**

1. जबकि समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 24 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/14/2005-डीजीएडी द्वारा मूल जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/14/2005-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइपों" (जिसे यहां आगे डीआई पाइप एवं संबद्ध सामान भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क भारत सरकार द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डक्टाइल आयरन पाइपों के आयातों पर 14 सितंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए थे।

2. जबकि सीमा प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार, जब तक लगाए गए पाटनरोधी शुल्क पूर्व में नहीं हटाए जाएंगे, उनके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएंगे। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार, प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए 07 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/1006/2012 द्वारा निर्णायक समीक्षा शुरू की कि क्या शुल्क बंद किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी।
3. और जबकि, 14 सितंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित किया गया मूल पाटनरोधी शुल्क भारत सरकार द्वारा 13 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 41/2012-सीमा शुल्क द्वारा 12 सितंबर, 2013 तक बढ़ाई गई थी।
4. और जबकि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हुए 04 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए। निश्चायत्मक पाटनरोधी शुल्क भारत सरकार द्वारा 10 अक्तूबर, 2013 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए थे।
5. और जबकि, मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड, मैसर्स श्रीकलास्ती पाइप्स लि. (एसपीएल) और मैसर्स ज़िंदल सॉ लिमिटेड ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू किए जाने के लिए 31.03.2018 को आवेदन पत्र दायर किया।
6. और जबकि, याचिकाकर्ताओं को उनका मामला प्रस्तुत करने तथा अनुरोध करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष 15.05.2018 को जांच की शुरुआत से पूर्व मौखिक सुनवाई का अवसर दिया गया था।
7. और जबकि, घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका की जांच तथा 15.05.2018 को सुनवाई के दौरान किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डीआई पाइपों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, प्राधिकारी के निर्णय को सूचित करते हुए 17.05.2018 का आदेश जारी किया गया था।
8. और जबकि, उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध घरेलू उद्योग ने अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का विशेष सिविल आवेदन पत्र संख्या 12368 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26.09.2018 और 08.10.2018 के आदेश द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी 17.05.2018 के आदेश को दरकिनारा कर दिया और प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे 09.10.2018 से पूर्व नए सिरे से निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लें।
9. और जबकि, गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 26.09.2018 के उपर्युक्त आदेश के निर्णय के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 09.10.2018 को निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में केंद्र सरकार ने 09.10.2018 की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 09 अप्रैल, 2019 तक शुल्क बढ़ा दिए।
10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के क्षेत्र में पूर्व की अधिसूचनाओं के सभी पहलू शामिल हैं।

#### **ख. प्रक्रिया**

11. इस अधिसूचना में अपनाई गई प्रक्रिया नीचे वर्णित की गई है:
  - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले घरेलू उद्योग से उपर्युक्त याचिका की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
  - ii. प्राधिकारी ने 09 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/18/2018 द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
  - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को 09.10.2018 की अधिसूचना की प्रति भेजी और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत सूचित करने के पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर दिया।

- iv. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास तथा संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/विनिर्माताओं को याचिका तथा निर्यातक प्रश्नावली की प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराएं।
1. योंगटोंग डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कं. लि.
  2. बेंक्सी बैतई डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कं. लि.
  3. बैतई आयरन एंड स्टील ग्रुप कं. लि.
  4. चेंगदू जिनफेंग
  5. डालियन वानटोंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कं. लि.
  6. हाइडेरा मशीनरी लिमिटेड
  7. क्वांशी जिनथांग डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कं. लि.
  8. रिझाओ झुफु इंडस्ट्री कं. लि.
  9. शानडोंग डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कं. लि.
  10. शंघाई कास्ट आयरन पाइप प्लांट
  11. शांक्सी सॉलिड गुआंगुआ कास्ट पाइप कं. लि.
  12. शांक्सी सॉलिड इंडस्ट्रियल कं. लि.
  13. जिनजियांग ट्रेजरी डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कं. लि.
  14. जिनजिंग डक्टाइल पाइप्स (ग्रुप) कं. लि.
  15. सैंट गोवेन (जुझोऊ) पाइप कास्टिंग कं. लि.
- v. एक पूरक प्रश्नावली संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि वे निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराएं।
- vi. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उस देश के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों, जिनकी प्राधिकारी को जानकारी नहीं थी, को यह सलाह दें कि वे जांच की शुरुआत तथा निर्यातक प्रश्नावली का निर्धारित समय के भीतर उत्तर दें। जो पत्र, याचिका और निर्यातक प्रश्नावली ज्ञात निर्यातकों को भेजी गई थी, उसकी एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई।
- vii. संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को आयातक प्रश्नावली भेजी:
1. प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  2. जे बी गोकल एंड कं. प्रा. लिमिटेड
  3. गम्मोन इंडिया लिमिटेड
  4. लारसेन एंड टुब्रो लिमिटेड
  5. एसपीएमएल इंडिया लिमिटेड
- ix. उपर्युक्त किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्नावली का अथवा जांच की शुरुआत का उत्तर नहीं दिया।

- x. जांच 01 जनवरी, 2017 से शुरू करके 31 दिसंबर, 2017 (12 माह) अर्थात् जांच की अवधि (पीओआई) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि शामिल थी।
- xi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अन्य अनुरोधों तथा याचिका के अगोपनीय रूपांतर को प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा और उसे नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार समय-समय पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखा।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।
- xiii. जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच में संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xiv. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 25.01.2019 को एक मौखिक सुनवाई की गई थी जिसमें घरेलू उद्योग और उनके अटॉर्नी ने मौखिक रूप से अपने विचार दिए। इसके बाद उनके लिखित अनुरोध आए थे।
- xvi. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का स्थल सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- xvii. जांच की अवधि के लिए और पूर्व के तीन वर्षों के लिए आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए थे।
- xviii. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xix. इस जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर संगत सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार 1 अमेरिकी डॉलर = 66.04 रुपए है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

##### घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

12. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व जांच में है अर्थात् डकटाइल आयरन स्पन पाइप है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो कि मूल जांच में है।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और चीन जन. गण. में उत्पादित तथा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई अंतर नहीं है और वे नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार समान वस्तु हैं।
- iii. संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादकों और चीनी उत्पादकों द्वारा लगाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

13. विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

14. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"अंतर्राष्ट्रीय मानक की धारा 3.1 तथा 3.2, आईएसओ 2531 (पानी और गैस के लिए) तथा आईएसओ: 7186 (सीवेज अनुप्रयोगों के लिए) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद डक्टाइल आयरन स्पन पाइप है। इन्हें प्रायः स्फेराइडर ग्रेफाइट आयरन पाइप अथवा डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप अथवा डक्टाइल आयरन स्पन पाइप के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ये सीमा प्रशुल्क अधिनियम के 73030030 और 73030090 के अंतर्गत भी वर्गीकरणीय हैं।"

डीआई पाइपों के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नलिखित में हैं:

- क. उच्च दाब पर कच्चे, वहनीय और समुद्री पानी का पारेषण।
- ख. वहनीय जल और गैस का वितरण।
- ग. घरेलू एवं औद्योगिक बहिस्त्राव का निपटान।
- घ. अग्निशमन प्रणालियां।

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्णायक समीक्षा होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित डीआई पाइप और चीन जन. गण. द्वारा उत्पादित पाइप पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार "समान वस्तु" हैं।

**घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार****घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) संबद्ध सामानों के आवेदक का उत्पादन हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 54 प्रतिशत है और समर्थकों के साथ उत्पादन का लगभग 89 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि आवेदक का देश में कुल घरेलू उत्पादन का भारी अनुपात है।
- (ii) इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

18. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

19. यह नोट किया जाता है कि आवेदकों अर्थात् मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड, मैसर्स श्रीकलास्ती पाइप्स लि. (एसपीएल) और मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड का कुल भारतीय उत्पादन में 54 प्रतिशत हिस्सा है और समर्थकों के साथ उनका कुल भारतीय उत्पादन का 89 प्रतिशत है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदकों का भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में भारी अनुपात है।

20. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदकों ने न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हैं। अतः जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

**ड. विविध अनुरोध****घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

21. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बहुत प्रभावी रहे हैं और भारत में डीआई पाइप उद्योग के बने रहने और उसकी वृद्धि में उनसे मदद मिली है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यह तथ्य कि पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुए हैं, उनके इस तर्क का प्रमाण है कि चीनी सामान यदि उचित और अपाटित कीमतों पर आयातित किए जाते हैं तो प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं।

22. यह एक रिकार्ड का मामला है कि किसी भी चीनी निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया अथवा यह सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया कि शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को कोई क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली भाग-II में किसी भी निर्यातक से कोई सूचना प्राप्त न होने अथवा चीन सरकार से भी कोई सूचना न मिलने की स्थिति में प्राधिकारी को वर्तमान शुल्क जारी रखने की सिफारिश करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सूचना तथा आंकड़े प्रदान किए गए हैं कि शुल्क जारी न रखे जाने की स्थिति में क्षति होने की पूरी-पूरी संभावना है। इसके मद्देनजर हम प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे कृपया घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्क बढ़ाएं।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

23. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा का प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना है और इस प्रयोजन के लिए सभी संगत सूचना की जांच की जानी है।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों में उठाए गए प्रत्येक संगत मुद्दे को इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर लिया जाएगा।

**च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का सिद्धांत तथा निर्धारण, पाटन की संभावना****सामान्य मूल्य से संबंधित अनुरोध****घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

26. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

(ii) चूंकि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिसों का उत्तर नहीं दिया है, अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर इस कारण नहीं निर्धारित किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए प्राधिकारी को उस तीसरे देश में सहयोगी उत्पादक द्वारा की गई पूरी घरेलू बिक्री के संबंध में पूर्ण एवं सत्यापन योग्य सूचना की आवश्यकता होगी जिसमें उसकी उत्पादन लागत तथा अन्य सभी संबंध सूचना और साक्ष्य (साधारण व्यापार प्रक्रिया में समस्त सूचना सहित) भी होगी। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के तहत निर्धारित उचित तुलना के सिद्धांत भी इस संबंध में संगत हैं।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

27. सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के कोई अनुरोध नहीं थे।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

28. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सक्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

29. अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि एक उप पैराग्राफ (क)(ii) के उपबंध चीनी अभिगम की तारीख से 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के उपबंध 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए।

30. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ के साथ हस्ताक्षरित अभिगम नयाचार के पैरा 15(क)(i) के तहत प्रतिबद्धताओं में यह अपेक्षित है कि जांच के तहत उत्पादकों को स्पष्ट रूप से यह दर्शाना चाहिए कि विनिर्माण, उत्पादन और उस उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। यह सिद्ध होने की स्थिति में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य तुलनात्मक रूप से कीमत निर्धारण करने में जांच के अधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 तथा भारत की पाटनरोधी नियमावली में यह अपेक्षित है कि उत्पादक/निर्यातक के वित्तीय रिकार्ड उपयुक्त रूप से उत्पादन लागतें दर्शाए। अतः निम्नलिखित के संबंध में उसकी सूचना तथा समर्थक साक्ष्य दिए जाने की आवश्यकता है।

क. कच्ची सामग्री प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश सहित कीमत, लागत, इनपुट के संबंध में निर्णय बाजार संकेत के अनुरूप किए जाते हैं जिनमें आपूर्ति एवं मांग दर्शाई जाए तथा जो बिना महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के होते हैं और क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती है।

ख. उत्पादन लागत तथा वित्तीय स्थिति को किसी ह्रास से कोई नुकसान नहीं होता।

ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी सुनिश्चितता तथा स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ. विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

31. इस जांच में प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को उन्हें यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी थीं कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना प्रदान करें। प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक ने कोई अनुरोध किया है। चीनी उत्पादकों/ निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करते हैं।

32. निर्मित सामान्य मूल्य \*\*\* प्रति मी. टन (\*\*\*) अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन) के रूप में निर्धारित किया जाता है।

### निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन से टर्की को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के आधार पर, एफओबी कीमत संदर्भ में वियतनाम और श्रीलंका के लिए भारत में संभावित निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए आगे निकाली जा सकती है। उपर्युक्त मानदंड के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित भारत को संभावित निर्यात कीमत निम्नलिखितानुसार है:

	यूनिट	श्रीलंका*	टर्की*	वियतनाम*
मात्रा	मी. टन	11838	7982	28923
एफओबी कीमतें	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए	66.04	66.04	66.04
एफओबी कीमतें	रु./मी. टन	***	***	***
कमीशन	रु./मी. टन	***	***	***
बैंक प्रभार	रु./मी. टन	***	***	***
पत्तन व्यय	रु./मी. टन	***	***	***
अंतर्देशीय भाड़ा व्यय	रु./मी. टन	***	***	***
वैट	रु./मी. टन	***	***	***
क्रेडिट लागत	रु./मी. टन	***	***	***
भारतीय रुपए में निवल निर्यात कीमत	रु./मी. टन	***	***	***
अमेरिकी डॉलर में निवल निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***	***	***
सामान्य मूल्य	रु./मी. टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	रु./मी. टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज	45-55%	60-70%	55-65%

\* चीन निर्यात आंकड़ों पर आधारित (स्रोत: एचएस इंटरनेशनल इंक. सिडनी)



**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

34. निर्यात कीमत के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान चीन से संबद्ध सामानों का आयात 154000 रुपए प्रति मी. टन पर 73 मी. टन तक है। यह भी नोट किया जाता है कि आयात की कीमत असामान्य है जो कि इस तथ्य से सिद्ध है कि घरेलू उद्योग लगभग \*\*\* रुपए प्रति मी. टन पर ही संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहा है। यह नोट किया जाता है कि इस मद के आयात आंकड़े या तो आयात मद के गलत वर्गीकरण हैं अथवा ये समान वस्तु नहीं हैं। तथापि, प्राधिकारी ने भी उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का परिकलन किया है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा और अप्रत्यक्ष कर (वैट) के लिए समायोजित किया गया है जो कि व्यापार के समान स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को रखने के लिए भारत को सामग्री का निर्यात करने हेतु निर्यातक द्वारा किया गया होता। निर्धारित की जाने वाली निर्यात कीमत \*\*\* रुपए प्रति मी. टन है।

विवरण	यूनिट	भारत को
निर्मित सामान्य मूल्य	रु./मी. टन	***
कारखानागत निर्यात कीमत	रु./मी. टन	119895
पाटन मार्जिन	रु./मी. टन	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	रैंज	(75) – (65)

**छ. क्षति का मूल्यांकन तथा कारणात्मक संपर्क की जांच****क्षति का मूल्यांकन****घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

36. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) चूंकि, क्षति की अवधि के दौरान अथवा क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का कोई विश्वसनीय आयात नहीं हुआ है, अतः वर्तमान क्षति का कोई क्षति विश्लेषण करना संभव नहीं हो सकता। किसी भी दशा में वर्तमान क्षति का विश्लेषण कोई आयात न होने पर व्यावहारिक रूप से निर्णायक समीक्षा के मामले में महत्वहीन हो जाता है।

(ii) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी के लिए कानून का अधिदेश संभावित विश्लेषण करना ही है, जैसा कि धारा 9क(5) में परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान चीनी निर्यातक द्वारा अन्य देशों को किए गए निर्यातों के आंकड़े देने में सक्षम रहा है। इस बात का पर्याप्त संकेत है कि यदि अन्य देशों को निर्यात कीमत भारत को संभावित निर्यात कीमत के आंकलन के रूप में ली जाती है (पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में), यह स्पष्ट होगा कि चीनी निर्यात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाएंगे। कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री का विश्लेषण यह दर्शाएगा कि यदि शुल्क नहीं बढ़ाए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति आसन्न है।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

37. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने जांच में भाग नहीं लिया और तदनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का बहुत कम आयात हुआ है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की तर्कसंगत मात्रा के अभाव के बावजूद प्राधिकारी संगत प्रक्रिया के अनुसार क्षति संबंधी विश्लेषण करने हेतु निर्धारण करते हैं।

### पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा कीमत प्रभाव

39. प्राधिकारी नियमावली के अनुसार नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करना अपेक्षित है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे आयातों की गैर-प्रतिनिधिकारक कीमत के साथ संबद्ध देश से आयात की अपर्याप्त मात्रा और वह भी ऐसे आयात की गैर प्रतिनिधि कीमत के मद्देनजर कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के संबंध में विश्लेषण अतार्किक निष्कर्ष दे सकता है और तदनुसार प्राधिकारी पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और कीमत प्रभाव के संबंध में विश्लेषण नहीं करने का निर्णय लेते हैं।

### घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

40. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच में शामिल होगा। नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

*"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"*

### उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

41. घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के संदर्भ में नहीं की जा सकती क्योंकि पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का बहुत कम आयात है। तथापि, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा को निम्नलिखित रूप में नोट करते हैं:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता-घरेलू उद्योग	मी. टन	***	***	***	***
उत्पादन-घरेलू उद्योग	मी. टन	***	***	***	***
क्षमता उपयोग-घरेलू उद्योग	%	82.26%	87.18%	85.07%	88.29%
घरेलू बिक्री-घरेलू उद्योग	मी. टन	***	***	***	***
घरेलू बिक्री-अन्य	मी. टन	335967	475089	744254	752115
सभी स्रोतों से आयात	मी. टन	3	365	22	408
कुल मांग (मी. टन)	मी. टन	934053	1207040	1528188	1576776

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 2015-16 में अपनी क्षमता बढ़ाई और उसके बाद वह समान रही। घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2015-16 में काफी वृद्धि हुई और उसके बाद उसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया।
- उसने यह भी देखा है कि भारत में अन्य उत्पादकों की बिक्री भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ी है।

### लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ

43. घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय निम्नलिखित थी:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
लाभ/हानि (रु./मी. टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	134	114	121
निवेश पर आय	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	157	101	130
नकद लाभ (रु./मी. टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	98	92	97

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग लाभ कमाता रहा है। तथापि, उसकी लाभप्रदता पूरी क्षति जांच अवधि में घटती-बढ़ती रही है।
- निवेश पर आय के मामले में भी समान प्रवृत्ति देखी गई है।

#### रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

45. घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, दी गई मजदूरी और उसकी उत्पादकता निम्नलिखित दर्शाती है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
उत्पादन (मी. टन)	765030	924132	901709	935868
प्रवृत्ति	100	121	118	122
कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	103	101	99
उत्पादन/कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	118	117	123
मजदूरी/कर्मचारी/वार्षिक	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	115	163	168

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- 2015-16 में आरंभिक वृद्धि के बाद प्रति कर्मचारी उत्पादकता जांच की अवधि में और वृद्धि होने से पूर्व 2016-17 के दौरान कुल मिलाकर समान रही है।
- प्रति कर्मचारी मजदूरी पूरी क्षति जांच अवधि में बढ़ी।

#### मालसूची

47. घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
औसत स्टॉक (मी. टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	172	223	216
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार मालसूची	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	142	189	176

48. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची जांच की अवधि के दौरान आंशिक गिरावट को छोड़कर पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान बढ़ी।

### पूँजी जुटाने की क्षमता

49. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाते हैं तो उसकी स्थिति और बुरी हो जाएगी और परिणामस्वरूप बाजार से अथवा वित्तीय संस्थाओं से पूँजी जुटाने में कठिनाईयां होंगी।

### वृद्धि

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत कम है और इसीलिए घरेलू उद्योग की वृद्धि और आयातों के बीच वस्तुपरक रूप से कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

### झ. कारणात्मक संपर्क की जांच

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि:

(i) यह कानून की तय स्थिति है कि निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संपर्क विश्लेषण अनिवार्य रूप से किए जाने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में घरेलू उद्योग मैक्सिको से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स (02 नवंबर, 2005 की डब्ल्यूटी/डीएस282/एबी/आर) के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय से निम्नलिखित उद्धरणों की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हैं:

"118. अतः हम मैक्सिको के साथ सहमत हैं कि यह मूलभूत सिद्धांत जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI में तथा पाटनरोधी करार के विभिन्न प्रावधानों में व्यक्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सिद्धांत पर प्रश्न नहीं उठाता। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत की गई "समीक्षा" में नए सिरे से सिद्ध किए जाने की अपेक्षा है। यह इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 11.3 में निर्धारित "समीक्षा" मूल जांच से "भिन्न" प्रयोजन के साथ "भिन्न" प्रक्रिया है।"

119. अपीलीय निकाय ने उल्लेख किया है कि "निर्णायक समीक्षा में किए जाने वाले निर्धारण की प्रकृति मूल जांच में किए जाने वाले निर्धारण की प्रकृति से कुछ अनिवार्य संबंधों में भिन्न होती है।" और यह कि "[टी] मूल जांच पर लागू अनुशासन समीक्षा प्रक्रियाओं में स्वतः आयातित नहीं किए जा सकते।"

### X. जांच परिणाम एवं निष्कर्ष

219. इस रिपोर्ट में निर्धारित कारणों से अपीलीय निकाय:

(क) कारणात्मकता के संबंध में:

(i) यह पाते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत निर्णायक समीक्षा निर्धारण में एक कानूनी दायित्व के मामले में संभावित पाटन एवं संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है

और यह कि इसीलिए यूएसआईटीसी को इस विभाग में मुद्दे पर निर्णायक समीक्षा में अपने क्षति निर्धारण की संभावना बनाने में ऐसा संपर्क दर्शाने की आवश्यकता नहीं थी।

(ii) यह भी अनुरोध किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा मामले में कारणात्मक संपर्क की आवश्यकता लागू न करने के लिए अच्छे तकनीकी और तार्किक कारण हैं। यदि आयात न होने पर भी शुल्क बढ़ाए जाते हैं तो कारणात्मक विश्लेषण करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, धारा 9क(5) के तहत शुल्कों की अवधि बढ़ाए जाने के लिए परीक्षण केवल यह जांच करने के लिए है कि क्या इस प्रकार का शुल्क बंद किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

52. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

53. कारणात्मक संपर्क के संबंध में नियमावली के अनुबंध 2 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"यह दर्शाया जाना चाहिए कि पाटित आयात पाटन के प्रभाव के माध्यम से उपर्युक्त पैरा (ii) तथा (iv) में निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संगत साक्ष्य की जांच के आधार पर होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी उन पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारक की भी जांच करेंगे जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं और इन अन्य कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए। जो कारक इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन एवं घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।"

54. जहां तक अन्य कारकों से हुई क्षति के विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

### **पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य**

55. पूरी क्षति अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का बहुत कम आयात है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से आयातों की मात्रा भी अपर्याप्त है। अतः आयातों की मात्रा और मूल्य तथा घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

### **मांग में संकुचन**

56. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई नकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इसके बजाए वह बढ़ी है और उसने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। इस प्रकार, मांग में संकुचन कोई संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

### **खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

57. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

### **व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

58. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

### **प्रौद्योगिकी में विकास**

59. उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही आगामी भविष्य में परिवर्तन होने की कोई संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।

### **निर्यात निष्पादन**

60. याचिकाकर्ता कंपनियाँ विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करती हैं। तथापि, घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना को क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार में नहीं लिया गया है।

### झ. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

61. निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में नए कारणात्मक संबंध की जांच की जरूरत नहीं होने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के बावजूद प्राधिकारी कारणात्मक संबंध की जांच करने की कार्रवाई करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभ, निवेश पर आय, उत्पादन और बिक्री में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है और तदनुसार घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।

### ञ. पाटन एवं क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

62. पाटन के जारी रहने/बार-बार होने तथा क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन से कोई भी निर्यात यह सिद्ध नहीं करते कि चीनी निर्यात तब तक भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते जब तक वे पाटन क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होते। तथापि, यह कहा जा सकता है कि यदि अनुपयुक्त क्षमता को देखते हुए शुल्क नहीं बढ़ाए जाते तो भारी संभावित आयातों की पूरी संभावना है।

(ii) वर्तमान शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के संभावित पाटन के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए जारी रखा जाना है। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान अथवा पूर्व वर्षों में संबद्ध सामानों का कोई निर्यात नहीं हुआ है। अतः घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग सहित अन्य उपयुक्त तीसरे देश को चीन से उपर्युक्त सामानों की निर्यात कीमतों के आधार पर भारत में संभावित निर्यात कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग द्वारा किसी पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी नियमावली और न्याय में पर्याप्त संकेतों का प्रावधान है कि जब वह तीसरे देश की कीमतों में आता है तो प्रयोग किए जाने के लिए "उपयुक्तता" मानदंड है।

(iii) घरेलू उद्योग ने चीन से वियतनाम, श्रीलंका और टर्की जैसे प्रतिनिधि देशों को डीआई पाइपों की एफओबी निर्यात कीमतों के आधार पर भारत को संभावित कीमतों का भी अनुरोध किया है। अनुरोध है कि ये देश विकासात्मक प्रयासों और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं में भारत के समान हैं। चूंकि, इन देशों का डीआई पाइपों का कोई घरेलू उत्पादन नहीं है और इसीलिए इन देशों को पेश किए गए पाइप उपयुक्त रूप से सही माने जा सकते हैं तथा भारत में संभावित कीमतों को उचित रूप से दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में कीमत आकर्षकता का विश्लेषण करने के लिए चीन से अन्य देशों को सभी निर्यात लेन-देनों को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन भी किया है। समग्र आंकड़ों से घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यदि सामान दूसरे देशों को निर्यात कीमत के आधार पर पहुँच मूल्य पर भारत में आने शुरू होते हैं तो घरेलू उद्योग को निश्चित रूप से हानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी।

(iv) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि चीन से अन्य देशों को निर्यातित 70 प्रतिशत मात्रा उस कीमत पर है जिसका सकारात्मक क्षति मार्जिन होता और अन्य देशों को बेची गई लगभग 83 प्रतिशत मात्रा पाटित कीमतों पर है। यह निसन्देह सिद्ध करता है कि ऐसी पूरी संभावना है कि इन कीमतों पर, यदि अतिरिक्त क्षमता भारत की ओर की जाती है, वह घरेलू उद्योग को क्षति आसन्न है।

(v) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध है कि किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक अथवा यहां तक कि चीनी सरकार ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई विस्तृत सूचना और साक्ष्यों का विरोध नहीं किया है। यह गैर-प्रतिभागिता केवल यह सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना विरोधात्मक है और प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग करने के लिए विवश हैं।

(vi) घरेलू उद्योग ने संबंधित कंपनियों की वेबसाइट से सूचना तथा चीन में उपलब्ध क्षमताओं के संबंध में वेबसाइट से उपलब्ध सूचना का न्यूनीकरण किया है। घरेलू उद्योग के अनुरोधों के अनुसार चीन में अतिरिक्त क्षमता भारत में कुल घरेलू मांग से अधिक है। चीन में संबद्ध सामानों की क्षमता घरेलू उद्योग की क्षमता से तिगुनी से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों की चीनी क्षमता भारत में मांग और घरेलू उद्योग के उत्पादन का क्रमशः 4.6 गुना और 4.2 गुना है। इसके व्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	संयंत्र	क्षमता
1	जिंग जिंग पाइप कं. (4 संयंत्र)	1800000
2	बेंक्सी बैतई पाइप कं.	600000
3	लांगखाऊ फैनलिन पाइप कं.	250000
4	सैंट गोबेन (जुझोऊ) पाइप कास्टिंग कं. लि.	1700000
5	डलियन कुंडा पाइप कं. (2)	200000
6	जिनचेंग चुनचेन पाइप कं.	180000
7	सन पाइप कं.	150000
8	जुझोऊ एवरब्राइट (एसजीपीएएम)	200000
9	शानडोंग जिनान पाइप कं.	300000
10	हेनन ऑयांग पाइप कं.	300000
11	शांक्सी शेनजिनन पाइप कं.	100000
12	रिझोन झु पाइप कं.	200000
13	क्यांशी जिनथांग आयरन पाइप्स कं. लि.	90000
14	शांक्सी गुआंगुआ कास्ट पाइप	300000
15	योंगटोंग डक्टाइल कास्ट लि.	400000
16	जिनजियांग ट्रेजरी कं. लि.	200000
17	लघु संयंत्रों की संयुक्त क्षमता (लगभग 15)	300000
	<b>कुल जोड़</b>	<b>72,70,000</b>

(vii) घरेलू उद्योग ने शुल्क हटाए जाने की स्थिति में देश में पाटित आयातों की आसन्न संभावना तथा संभावित खतरे को दर्शाने के लिए भारत में क्षमताओं, उत्पादन, बिक्री और मांग से चीन में उपर्युक्त क्षमताओं की तुलना भी दी है। यह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	
चीनी क्षमता (मी. टन)	72,70,000
घरेलू उत्पादकों की क्षमता (मी. टन)	22,35,000
भारत में मांग (मी. टन)	15,76,776
घरेलू उद्योग का उत्पादन (मी. टन)	17,24,624
घरेलू उद्योग की बिक्री (मी. टन)	15,76,368
घरेलू उद्योग की क्षमता के प्रतिशत के रूप में चीनी क्षमता (%)	325%
भारत में मांग के प्रतिशत के रूप में चीनी क्षमता (%)	461%
घरेलू उद्योग के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में चीनी क्षमता (%)	422%
घरेलू उद्योग की बिक्री के प्रतिशत के रूप में चीनी क्षमता (%)	461%

(viii) घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि चीन में संबद्ध सामानों की क्षमता घरेलू उद्योग की क्षमता के तीन गुना से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों की चीनी क्षमता भारत में मांग और घरेलू उद्योग के उत्पादन का क्रमशः 4.6

गुना और 4.2 गुना है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि यदि ये मात्राएं संभावित कीमतों पर भारत को भेजी जाती हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति आसन्न है।

(ix) अन्य देशों को निर्यात कीमतें चीन से निर्यातकों के संभावित व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, निविदा बोली जीतने के लिए यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो उत्पादक/निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री भारत में घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर करेंगे। यह स्थिति होने पर कीमत कटौती का बढ़ा हुआ स्तर आसन्न है।

(x) संभावित निर्यात कीमत के आधार पर परिकलित पाटन मार्जिन 50 प्रतिशत – 67 प्रतिशत की रेंज में है। ऐसी स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। शुल्क हटाए जाने से पाटित एवं अलाभप्रद आयातों का स्वतंत्र रूप से आना प्रोत्साहित होगा जिससे निश्चित रूप से घरेलू बिक्री कीमत, बाजार हिस्सा और अंततः घरेलू उद्योग के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(xi) घरेलू उद्योग इस बात को दोहराता है कि चीनी उत्पादक तब तक प्रतिस्पर्द्धी नहीं है जब तक वे पाटन की परिपाटियों में लिप्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी का वर्तमान स्तर सीआईएफ मूल्य के लगभग 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत ही है जो किसी भी मानक से बहुत सामान्य है। इसके बावजूद, किसी भी निर्यातक ने संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और न ही उन्होंने ग्राहकों द्वारा दी गई किसी निविदा में भाग लिया है।

### हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

63. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है जो निम्नलिखित रूप में है:

(vii) वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।

तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) के तहत संभावना के पहलू पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:

### 1. वर्तमान एवं जारी आयात

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात केवल 73 मी. टन है। घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह भी अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद ही उत्पाद की प्रकृति के कारण होने वाले संबद्ध सामानों के किसी आयात की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोई भी चीनी उत्पादक/निर्यातक भारत में डकटाइल आयरन पाइप की आपूर्ति के लिए किसी संविदा में भाग लेता हुआ नहीं समझा जाता। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की अकेली काफी वृद्धि को छोड़ दें तो आयातों की वृद्धि का इस प्रकार कोई प्रश्न नहीं है।



## 2. कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त के मद्देनजर कि घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव डालने वाले आयातों का कोई प्रश्न नहीं है।

## 3. अधिशेष क्षमताएं

वास्तविक क्षति के खतरे को सुनिश्चित करने वाले इस मानदंड में भारतीय बाजार में निपटान योग्य मात्रा को भेजने की संभावना का पता लगाने के लिए मौजूदा अधिशेष क्षमताओं और क्षमता अभिवृद्धि, यदि कोई है, के मूल्यांकन की अपेक्षा है।

शुल्क हटाए जाने की स्थिति में अधिशेष क्षमता तथा भारत में उसका इस्तेमाल करने की संभावना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि केवल अधिशेष क्षमता की मौजूदगी भारत में अधिशेष उत्पादन को भेजने की संभावना सिद्ध नहीं करती और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाएं तो आयातों की संभावना सिद्ध नहीं करती।

## 4. मालसूची का स्तर

संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध मालसूची का स्तर पर्याप्त सहयोग के अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

### ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

65. याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

(क) संबद्ध वस्तु के आयात के अभाव में प्राधिकारी के लिए पाटन की संभावना और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विश्लेषण के लिए आयातों की संभावित कीमत पर विचार करने का दायित्व है। प्रकटन विवरण में पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है जिसके लिए उनके अनुरोध में विस्तृत सूचना दी गई है।

(ख) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिसमें चीन की सरकार, चीन के उत्पादक और निर्यातक शामिल हैं, को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद निर्विवाद बना हुआ है। यह भी अनुरोध किया गया है कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध/साक्ष्य स्वीकार करने चाहिए थे। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि हितबद्ध पक्षों के अलावा, प्राधिकारी ने भी प्रकटन विवरण में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो घरेलू उद्योग के अनुरोध/सूचना/साक्ष्य का खंडन या परिसमापन कर सके।

(ग) प्राधिकारी ने पैरा 34 में किसी उत्पाद की निर्यात कीमत पर विचार करने का प्रस्ताव किया है जो स्वीकृत रूप से समान वस्तु नहीं है या जिसकी असामान्य कीमतें हैं। यह बात पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 की पूर्णतः विरोधाभासी होगी। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि निर्यात कीमत और उसके बाद पाटन मार्जिन के परिकलन का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वह संबद्ध वस्तु के लिए नहीं है और इसलिए प्राधिकारी को ऐसी सूचना पर अपना निष्कर्ष आधारित नहीं करना चाहिए जो संबद्ध वस्तु के समान वस्तु न हो।

(घ) प्राधिकारी ने चीन से अन्य देशों को वास्तविक निर्यात आंकड़ों के आधार पर संभावित पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर भी विचार नहीं किया है। प्राधिकारी को विधिक दायित्व निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन की संभावना की जांच करना है और प्राधिकारी से उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत सूचना के लिए अंतिम जांच परिणामों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

(ङ) जब प्राधिकारी ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला है कि संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान समान वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है तो कोई सार्थक क्षति विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी से वर्तमान क्षति सूचना पर आधारित कोई निष्कर्ष निकालने से बचने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि वह तार्किक नहीं है या उसकी कानूनी प्रासंगिकता नहीं है।

(च) कि भारत में आयात में संभावनाओं के संबंध में घरेलू उद्योग की दलील को पूरी तरह से गलत समझा गया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया है कि चीन से आयातों की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग ने दोहराया है कि कोई आयात संभावित नहीं है। यदि आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का भार डाल दिया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क देश में उचित बाजार कीमत बहाल रखने में कारगर है और यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क संरक्षण को जारी नहीं रखा जाता है तो पाटित कीमतों पर आयातों की निश्चित रूप से पुनरावृत्ति होगी। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से उनके अंतिम जांच परिणामों में पैरा 62 (1) में उल्लिखित आधार का लोप/संशोधित करने का भी अनुरोध किया है क्योंकि वह घरेलू उद्योग के अनुरोध की त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है।

(छ) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने चीन में भारी अतिरिक्त क्षमता की मौजूदगी को स्वीकार किया है। तथापि, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष का आधार प्रतीत नहीं हुए हैं जो भारत में अतिरिक्त क्षमताओं के पाटन की संभावना को सिद्ध करता हो। घरेलू उद्योग ने विधिक अपेक्षा पर भी संभावना या संभावना की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए ही ध्यान दिलाया है कि अतिरिक्त वस्तुओं के देश में प्रवेश करने की संभावना है। तथापि, प्रकटन विवरण से ऐसा लगता है कि प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित परीक्षण यह है कि घरेलू उद्योग अवश्य निस्संदेह यह सिद्ध करे कि अतिरिक्त क्षमता भारत में ही प्रवेश करेगी। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध भी किया है कि घरेलू उद्योग के कानूनी दायित्व के त्रुटिपूर्ण पाठ के आधार पर कोई निष्कर्ष गुमराह करने वाले और गलत नतीजे तक पहुंचा देगा। यह कि घरेलू उद्योग अधिक से अधिक चीन में अतिरिक्त क्षमता तथा भारतीय बाजार के आकर्षक होने के संबंध में सूचना दे सकता है। एक बार इन तथ्यों से तर्कसंगत रूप से साबित होने पर निश्चित निष्कर्ष यह होगा कि पाटित वस्तुओं के भारत में आने की पूरी संभावना है। यह अनुरोध भी किया जाता है कि प्राधिकारी इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने ऐसी कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया है जो घरेलू उद्योग के पूर्णतः समर्थित अनुरोधों का विरोध तो क्या परिसमापन भी कर सके।

(ज) यह कि प्रकटन विवरण में ए डी नियमावली के नियम 23 (1 ख) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (5) के अधीन यथापरिकल्पित संभावना विश्लेषण नहीं करता है। यह अनुरोध भी किया गया है कि प्राधिकारी ने संभावना शीर्ष के अधीन कतिपय कारकों के संबंध में कुछ विश्लेषण किया है जबकि वास्तविक क्षति का खतरा से संबंधित उक्त कारक तथा उनकी किसी संभावना का विश्लेषण नहीं किया गया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि खतरा संबंधी विश्लेषण की जांच को संभावना विश्लेषण के समतुल्य नहीं माना जा सकता है।

(झ) वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने इस तथ्य के समर्थन में विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य दिए हैं कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की पूरी संभावना है। यह साक्ष्य निर्विवाद भी हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद साक्ष्य तथा उनके विरोध में किसी साक्ष्य/अनुरोध के अभाव को ध्यान में रखते हुए पाटन तथा क्षति की संभावना के निष्कर्ष तक पहुंचने के मूल अवयव पर्याप्त हो जाते हैं।

(ट) प्राधिकारी को पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान समान वस्तु के वास्तविक आयातों के अभाव में भारत में संभावित कीमत के आधार पर संभावित कीमत संबंधी विश्लेषण करना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि संभावित कीमत और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव से संबंधित उनके अनुरोध पर प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में ध्यान नहीं दिया है। प्राधिकारी से इन सभी अनुरोधों पर विचार करने और उन पर पुनः टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

66. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

67. प्रकटन के पश्चात टिप्पणियों की जांच निम्नानुसार है :

- i. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना और पुनरावृत्ति का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में उचित स्थानों पर इस संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है।
- ii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के नगण्य आयात हुए हैं और इसलिए इतने कम आयातों के आधार पर भारतीय बाजार में कीमत के आकर्षक होने का विश्लेषण करना उचित नहीं होगा।
- iii. घरेलू उद्योग ने स्वयं यह अनुरोध किया है कि पी ओ आई के बाद भी निम्न के कारण संबद्ध वस्तु के किसी आयात की संभावना नहीं है (क) पाटनरोधी शुल्क लागू हैं और (ख) उत्पाद की प्रकृति क्योंकि चीन के उत्पादक/निर्यातक ने भारत में डकटाइल आयरन पाइप की आपूर्ति के लिए किसी संविदा में शामिल होने की जानकारी दी है। चूंकि पी यू सी के आयात क्षति अवधि के दौरान लगभग बंद हो गए हैं इसलिए ए डी नियमावली के अनुबंध II (vii) (क) के अनुसार क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के विश्लेषण हेतु भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की अधिक दर अपेक्षित है, जिसे पूरा नहीं किया गया है।
- iv. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यही तथ्य कि क्षति अवधि के दौरान पी यू सी के आयात में तेजी से गिरावट आई है, इस बात को सिद्ध करता है कि 23 अगस्त, 2007 से लागू पाटनरोधी उपाय ने अपना लक्षित प्रयोजन पहले ही पूरा कर दिया है और इसे आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
- v. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि चीन के निर्यातकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं तथापि, प्राधिकारी दोहराते हैं कि केवल अतिरिक्त क्षमता को जोड़े जाने को पाटन या क्षति की संभावना के निष्कर्षकारी साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है कि चीन में अतिरिक्त क्षमता को पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर भारत में आपूर्ति किया जाएगा।

**ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें**

68. घरेलू उद्योग की दलीलों पर विचार करने के बाद और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे नहीं बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।

**ड. आगे की प्रक्रिया**

69. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा मै. जिंदल पॉली फिल्म लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, डब्ल्यू.पी (सिविल) सं. 8202/2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2019

**FINAL FINDINGS**

**Subject: Final Findings in the Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of ‘Ductile Iron Pipes’ originating in or exported from China PR.**

**F.No.7/18/2018-DGAD.—A. Background of the case**

1. Whereas the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or the AD Rules or the Anti-Dumping Rules), had initiated the original investigation vide Notification No. 14/14/2005-DGAD dated 24th February, 2006. The Authority issued its Final findings recommending imposition of definitive anti-dumping duty on imports of Ductile Iron Pipes (hereinafter also referred to as DI Pipes or the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) vide Notification No.14/14/2005-DGAD dated 23rd August 2007. The definitive anti-dumping duties were imposed by the Government of India vide Customs Notification No. 103/2007-Customs dated 14th September 2007 on the imports of Ductile Iron Pipes originating in or exported from China PR.

2. Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duties imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. In terms of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the sunset review vide Notification No. 15/1006/2012 dated 7th September, 2012 to examine as to whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And whereas, the original antidumping duty as notified vide Notification No.103/2007-Customs dated 14th September, 2007 was extended by the Government of India up to 12th September, 2013 vide Notification No. 41/2012-Customs dated 13th September, 2012.

4. And whereas, the Authority issued its Final Findings vide notification no. 15/1006/2012-DGAD dated 4<sup>th</sup> September, 2013 recommending continuation of anti-dumping duties. The definitive anti-dumping duties were imposed by the Government of India vide Customs Notification No. 23/2013-Customs dated 10<sup>th</sup> October, 2013.

5. And whereas, M/s Electrosteel Casting Limited, M/s Srikalahasti Pipes Ltd. (SPL) and M/s Jindal Saw Limited file filed an application dated 31.03.2018 for initiation of Sunset Review investigation for continuation of existing Anti-Dumping Duty on the subject goods originating in or exported from the subject country.

6. And whereas, the petitioners were given the opportunity of oral hearing at pre-initiation stage before the Designated Authority on 15.05.2018 to present their case and make their submissions

7. And whereas, based on examination of the petition filed by the Domestic Industry and the submissions made during the hearing on 15.05.2018, Authority came to the conclusion that there was no need to initiate the Sunset Review concerning imports of DI Pipes originating in or exported from China and accordingly order dated 17.05.2018 was issued intimating the decision of the Authority.

8. And whereas against the said order, the Domestic Industry filed Special Civil Applications No. 12368 of 2018 before the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. The Hon'ble High Court vide its order dated 26.9.2018 and 8.10.2018 set aside the order dated 17.05.2018 issued by the Designated Authority and directed the Authority to decide the application for sunset review afresh well before 09.10.2018.

9. And whereas pursuant to the said orders of the Hon'ble High Court of Gujarat dated 26.09.2018 the Designated Authority initiated the sunset review investigation on 09.10.2018. In pursuance of the direction of the Hon'ble High Court of Gujarat, the central government extended the duties vide notification no. 51/2018-Customs (ADD) dated 09.10.2018 up to 9<sup>th</sup> April, 2019.

10. The scope of the present sunset review investigation covers all aspects of the previous notifications.

## **B. Procedure**

11. The procedure followed in this investigation has been described below:

- i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the aforesaid petition from the Domestic Industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. The Authority initiated sunset review investigation vide Notification No. 7/18/2018 dated 9th October, 2018.
- iii. The Authority forwarded copy of the Notification dated 09.10.2018 to the Embassy of the subject country in India, known exporters, importers/users and the Domestic Industry and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter communicating the initiation of the investigation in accordance with the Rule 6(2) of the Rules.
- iv. The Authority provided a copy of the petition as well as the exporter's questionnaire to the Embassy of the subject country in India and the following known exporters/manufacturers from the subject country in accordance with sub-rule (3) of Rule 6 supra with the request to provide relevant information to the Authority within the stipulated time:
  1. Yongtong ductile cast iron pipe Co., Ltd
  2. Benxi Beitai Ductile Cast Iron Pipe Co., Ltd
  3. Beitai Iron and Steel Group Co., Ltd
  4. Chengdu Jinfeng
  5. Dalian Wantong Industrial Equipment Co., Ltd
  6. Hydera Machinery Limited
  7. Qian'anishi Jintang Ductile Iron Pipes Co., Ltd.
  8. Rizhao Zhufu Industry Co., Ltd.
  9. Shandong Ductile Iron Pipes Co., Ltd
  10. Shanghai Cast iron Pipe Plant
  11. Shanxi Guanghua Cast Pipe Co., Ltd.
  12. Shanxi Solid Industrial Co., Ltd
  13. Xinjiang Treasury Ductile Iron Pipe Co., Ltd.
  14. Xinxing Ductile Iron Pipes (Group) Co., Ltd.
  15. Saint Gobain (Xuzhou) Pipe Casting Co., Ltd.
- v. A supplementary questionnaire was also provided to the known producers/exporters of the subject goods from the subject country and the Embassy of subject country in India with the request to provide relevant information to the Authority within the stipulated time.

- vi. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise other exporters/producers from that country who were not known to the Authority to respond to the initiation of investigation and the exporter's questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and the exporter's questionnaire which was sent to the known exporters was also sent to the Embassy of the subject country in India.
- vii. None of the exporters/producers from the subject country filed questionnaire response
- viii. The importer's questionnaire was sent to the following known importers/users/user associations of the subject goods in India for necessary information within the prescribed time in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - 1. Pratibha Industries Limited
  - 2. J V Gokal & Co. Pvt. Limited
  - 3. Gammon India Limited
  - 4. Larsen & Toubro Limited
  - 5. SPML India Limited
- ix. None of the above-mentioned importers/users/user associations or any other interested party responded to the questionnaire or the initiation notification.
- x. The investigation was carried out for the period starting from 1st January 2017 to 31st December 2017 (12 months), i.e., the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.
- xi. The Authority kept a non-confidential version of the petition and other submissions presented by various interested parties from time to time in the form of a public file maintained by the Authority and kept the same open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7) of the Rules.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xiv. The non-injurious price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of guidelines laid down under Annexure III of the AD Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xv. An Oral Hearing was held on 25.1.2019 by the Designated Authority, where Domestic Industry and their attorneys provided their views orally. This was followed by their written submission.
- xvi. On the spot verification of the data provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary by the Authority.
- xvii. The import data for the period of investigation and preceding three years was obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).

- xviii. \*\*\*\* in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xix. The exchange rate adopted by the Authority in this investigation is 1USD=66.04\*\* as per the relevant customs notification.

**C. Product Under Consideration and the Like Article**

**Submissions by the Domestic Industry**

12. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and the like article:

- (i) The product under consideration for the purpose of the present investigation is the same as in the earlier investigation i.e., Ductile Iron Spun Pipes. The present investigation being a sunset review, the scope of the product under consideration has to remain the same as that in the original investigation.
- (ii) There is no difference in subject goods produced by the domestic industry and the subject goods produced in and exported from China PR and they are like articles in terms of the Rule 2(b) of the Rules.
- (iii) There is no material difference in the production process employed by the Chinese producers and the Indian producers of the subject goods.

**Submissions by other interested parties**

13. No submission was made by other interested parties with regard to the scope of product under consideration or like article.

**Examination by the Authority**

14. In the original investigation, the product under consideration was defined as under:

"The product under consideration is Ductile Iron Spun Pipe as defined under clause 3.1 and 3.2 of International Standard, ISO 2531 (for water and gas) and ISO:7186 (for sewage applications). These are often also described as Spheroidal Graphite Iron Pipes or Ductile Cast Iron Pipes or Ductile Iron Spun Pipes. These are classifiable within 73030030 and 73030090 of the Customs Tariff Act.

The various applications of DI Pipes are in:

- a. Transmission of raw, potable and sea water at high pressures.
- b. Distribution of potable water and gas.
- c. Disposal of domestic and industrial effluents.
- d. Fire-fighting systems.

15. The Authority notes that this being Sunset review, the scope of the product under consideration remains unchanged. The Authority further holds that the DI pipes manufactured by the domestic industry and those produced in China PR are "like articles" in terms of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

**D. Scope of the Domestic Industry and Standing**

**Submissions by the Domestic Industry**

16. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the domestic industry and its standing:

- (i) The applicants' share of production of subject goods constitutes 54% of the total Indian production and around 89% of the production with supporters. This shows that applicants constitute a major proportion of the total domestic production in the country.

- (ii) Further, the applicants have not imported the subject goods from the subject country nor they are related to importer or exporter of subject goods from subject country.

17. In view of the above, petitioners constitute the eligible domestic industry in terms of Rule 2(b).

**Submissions by other interested parties**

18. No submission has been made by other interested parties with regard to the standing of the Domestic Industry.

**Examination by the Authority**

19. It is noted that the applicants namely, M/s Electrosteel Casting Limited, M/s Srikalahasti Pipes Ltd. (SPL) and M/s Jindal Saw Limited account for 54% of the total Indian production and together with supporters they account for 89% of the total Indian production. Therefore, the Authority holds that the applicants command a major proportion of the total domestic production of the subject goods in India

20. The Authority also notes that applicants have neither imported the subject goods, nor are they related to any importer or exporter of the subject goods. Therefore, for the purpose of this investigation the applicants satisfy the standing requirement and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

**E. Miscellaneous Submissions**

**Submissions by the Domestic Industry**

21. The Domestic Industry submitted that the existing anti-dumping duties have been very effective and helped survival and growth of the DI Pipe industry in India. Further, Domestic Industry submitted that the fact that there have been no imports during the entire injury investigation period is testimony to their contention that the Chinese goods are not competitive if imported at fair and un-dumped prices.

22. It is a matter of record that none of the Chinese exporters have cooperated in the investigation or made any effort to prove that there is no likelihood of recurrence or continuation of injury to the Domestic Industry in the event duties are revoked. Therefore, in the absence of any information from any of the exporters in the prescribed Exporter's Questionnaire Part II or even from the Government of China, the Authority should recommend continuation of the present duties as sufficient information and data has been provided by the Domestic Industry to establish that there is every likelihood of recurrence of injury in the event the duties are not continued. In view thereof, we humbly request the Authority to kindly extend the duties for further period of 5 years to safeguard the interests of the Domestic Industry.

**Submissions by other interested parties**

23. No submissions was made by any other interested party

**Examination by the Authority**

24. The Authority notes that the purpose of a sunset review is to examine as to whether there is any likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event the anti-dumping duties are revoked and for this purpose all the relevant information is to be examined.

25. The Authority notes that each relevant issue raised in the submissions of the Domestic Industry will be dealt with at appropriate places in this final findings.

**F. Methodology and Determination of Normal Value, Export Price & Dumping Margin Likelihood of Dumping**

**Submission relating to Normal Value**

**Submissions made by the Domestic Industry**

26. The Domestic Industry has made the following submissions:



- (i) Normal value for China PR has to be determined in terms of the provisions for non-market economy countries.
- (ii) Since no producer / exporter from China has responded to the notices issued by the Authority, Para 7 of Annexure I of the AD Rules should be followed by the Authority for the determination of Normal Value. Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. In order to arrive at Normal Value on this basis, the Authority shall require complete and exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country along with its cost of production and all other associated information and evidences (including all information in the ordinary course of trade). Principles of fair comparison as laid down under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement are also relevant in this respect.

#### **Submissions by other interested parties**

27. There was no submission from other interested parties in regard to normal value.

#### **Examination by the Authority**

28. The Authority also notes that Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:  
*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

29. Article 15 implies that provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire in 15 years from the date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11<sup>th</sup> December, 2016.

30. With regard to the submissions made by the petitioner, it is noted that the commitments under para 15(a) (i) of the Accession Protocol signed by China with WTO requires that the producers under investigation should clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product. In event of this being substantiated, the importing WTO member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability. Further Article 2.2.1.1 of WTO and AD Rules of India requires that the financial records of producer/exporter reasonably reflect the production costs. Therefore, information and supportive evidence thereof in respect of the following is required to be provided.

- a. Decisions in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labor, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant State interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
- b. Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
- c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

31. As a part of the proceedings in this investigation, the Authority had sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject country advising them to provide information in the form and manner prescribed. There has been no response to the questionnaire nor has there been any submission by the any of the Chinese producers/exporters. In the absence of cooperation from the Chinese exporters/producers, the Authority determines to construct the normal value on the basis of facts available.

32. The constructed normal value so determined is as Rs. \*\*\* per MT ( USD \*\*\* per MT)

### **Export Price and Dumping Margin**

#### **Submissions made by the Domestic Industry**

33. Domestic Industry has submitted that based on the actual exports price of subject goods from China to Turkey, Vietnam and Sri Lanka in FOB price terms can be worked forwards to get the likely export price to India. Likely export price to India calculated by the domestic industry based on the abovementioned criterion is as under:

	Unit	Sri Lanka*	Turkey*	Vietnam*
Quantity	MT	11838	7982	28923
FOB Prices	USD/MT	***	***	***
Exchange Rate	USD/INR	66.04	66.04	66.04
FOB Prices	RS/MT	***	***	***
Commission	Rs/MT	***	***	***
Bank Charges	Rs/MT	***	***	***
Port Expenses	Rs/MT	***	***	***
Inland Freight Expenses	Rs/MT	***	***	***
VAT	Rs/MT	***	***	***
Credit Cost	Rs/MT	***	***	***
Net Export Price in INR	Rs/MT	***	***	***

Net Export Price in US\$	US\$/MT	***	***	***
Normal Value	Rs/MT	***	***	***
Dumping Margin	Rs/MT	***	***	***
Dumping Margin	%	45-55%	60-70%	55-65%

\*Based on China export Data (Source: HS International Inc. Sydney)

#### **Submissions by other interested parties**

34. There was no submission from other interested parties in regard to export price

#### **Examination by the Authority**

35. The Authority notes that imports of subject goods from China during POI is to the tune of 73 MT at Rs. 1,54,000 per MT. It is further noted that the price of import is abnormal, which is established by the fact that the DI is selling the subject goods at approx. Rs. \*\*\* per MT only. It is noted that the import statistics of this item points to either misclassification of the import item or it not being the like article. However, the Authority has also calculated the export price based on the available import data. Export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, inland freight and indirect taxes (VAT) which may have been incurred by the exporter for exporting material to India, in order to put normal value and export price at the same level of trade. The export price to be determined is as Rs. \*\*\* per MT.

Particulars	Unit	To India
Constructed Normal Value	Rs/MT	***
Ex-factory price	Rs/MT	119895
Dumping margin	Rs/MT	***
Dumping margin	Range	(75)-(65)

#### **A. Assessment of Injury and Examination of Causal Link**

##### **Assessment of Injury**

##### **Submissions made by the Domestic Industry**

36. Domestic Industry has made following submissions:

(i) Since there have been no reliable imports of the subject goods either during the Period of Investigation or the injury investigation period, no injury analysis can possibly be made of current injury. In any case, the analysis of current injury recedes into insignificance in case of a sunset review practically when there are no imports.

(ii) Domestic Industry further submits that the mandate of the law for the Authority is only to carry out likelihood analysis as envisaged in Section 9A (5). Further, the Domestic Industry has been able to collect data of exports by the Chinese exporter to other countries during this period. There is sufficient indication that if the export price to other countries is taken as an estimate of the likely export price to India (once the anti-dumping duties are removed), it would be clear that the Chinese exports will injure the Domestic Industry. The price undercutting as well as price underselling analysis would reveal that if the duties are not extended, the injury to the domestic industry is imminent.

##### **Submissions made by other interested parties**

37. No other interested party has participated in the investigations and accordingly no submission been made by other interested parties.

### **Examination by the Authority**

38. The Authority notes that there have been miniscule imports of the subject goods during the injury investigation period. The Authority however notes that despite the absence of reasonable quantum of import, the Authority as per the consistent practice determines to conduct injury analysis.

### **Volume Effect and Price Effect of the dumped imports**

39. The Authority notes that as per the Rules, the Authority is required to do the analysis of the volume effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry to determine price undercutting, price underselling, price suppression and depression. The Authority however notes that in view of the insignificant quantum of import from the subject country and that too at non-representative price of such import, the analysis with regard to price undercutting, price underselling, price suppression and depression would throw illogical conclusion and accordingly the authority decides not to carry out analysis with respect to volume effect and price effect of the dumped imports.

### **Economic parameters relating to the domestic industry**

40. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows:

*“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments”*

### **Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

41. The effects of dumped imports on the domestic operation of the domestic industry cannot be examined in terms of total production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry as there are miniscule imports of the subject goods during the entire injury investigation period. However, the Authority notes capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry as under:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity-DI	MT	***	***	***	***
Production-DI	MT	***	***	***	***
Capacity Utilization-DI	%	82.26%	87.18%	85.07%	88.29%
Domestic Sales-DI	MT	***	***	***	***
Domestic Sales-Others	MT	335967	475089	744254	752115
Imports from all Sources	MT	3	365	22	408
Total Demand (MT)	MT	934053	1207040	1528188	1576776

42. The Authority notes that:

- i. The Domestic Industry increased its capacity in 2015-16 to meet the increasing demand and thereafter it has remained the same. The production of domestic industry has witnessed significant increase in 2015-16 and thereafter it has not witness any substantial change.
- ii. It is also seen that the sales of other producers in India has also increased in the POI as compared to the base year.

**Profits, Return on Investment and Cash Profit**

43. The profits, cash profit and return on investments earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market were as under: -

Year	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Profit/loss (Rs./MT)	***	***	***	***
Trend	100	134	114	121
Return on Investment	***	***	***	***
Trend	100	157	101	130
Cash Profit (Rs./MT)	***	***	***	***
Trend	100	98	92	97

44. The Authority notes that:

- i. Domestic industry has been earning profits. However, its profitability has kept on fluctuating throughout the injury investigation period.
- ii. Similar trend is observed in case of return on investment also.

**Employment, Wages and productivity**

45. The number of employees employed by the domestic industry, wages paid, and its productivity shows as follows:

Year	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Production (MT)	765030	924132	901709	935868
Trend	100	121	118	122
Employees	***	***	***	***
Trend	100	103	101	99
Production/employee	***	***	***	***
Trend	100	118	117	123
Wages/employee/annum	***	***	***	***
Trend	100	115	163	168

46. The Authority notes that

- (i) Productivity per employee after initial increase in 2015-16 has remained more or less same during 2016-17 before witnessing further increase during POI.
- (ii) Wages per employee increased throughout the injury investigation period.

**Inventories**

47. Inventory position of the domestic industry is given in the table below:

Year	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Average stock (MT)	***	***	***	***
Trend	100	172	223	216
Inventory as No. of days of Production	***	***	***	***
Trend	100	142	189	176

48. It is noted the average inventory of the domestic industry increased during the entire injury investigation period except marginal decline during POI.

**Ability to raise capital**

49. The domestic industry claims that its condition will worsen once the anti-dumping duties in force are withdrawn and consequently will have difficulties in raising capital from the market or from financial institutions.

**Growth**

50. The Authority notes that the volumes of imports from the subject country are miniscule and therefore no comparative analysis can be carried out objectively between the growth of domestic industry and imports.

**B. Examination of Causal Link:****Submissions made by the Domestic Industry**

51. The domestic industry submits that:

(i) It is a settled position of law that causal link analysis is not mandatorily required to be done in sunset review investigations. In this connection, the domestic industry invites the attention of the Authority to the following excerpts from the Appellate Body decision in the case of Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R dated 2 November 2005):

*"118. We therefore agree with Mexico that this fundamental principle is expressed in Article VI of the GATT 1994 and in various provisions of the Anti-Dumping Agreement. The United States does not question this principle per se. However, this does not mean that a causal link between dumping and injury is required to be established anew in a "review" conducted under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement. This is because the "review" contemplated in Article 11.3 is a "distinct" process with a "different" purpose from the original investigation."*

*119. The Appellate Body has underlined that "the nature of the determination to be made in a sunset review differs in certain essential respects from the nature of the determination to be made in an original investigation", and that "[t]he disciplines applicable to original investigations cannot, therefore, be automatically imported into review processes."*

**X. Findings and Conclusions**

*219. for the reasons set forth in this Report, the Appellate Body:*

*(a) in relation to causation:*

*(i) finds that there is no requirement to establish the existence of a causal link between likely dumping and likely injury, as a matter of legal obligation, in a sunset review determination under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and that, therefore, the USITC was not required to demonstrate such a link in making its likelihood-of-injury determination in the sunset review at issue in this dispute;"*

(ii) It is further submitted that there are good technical and logical reasons for not applying the requirement of causal link in a sunset review case. If duties can be extended even if there are no imports, the question of carrying out the causation analysis does not arise. Further, the test for extension of the period of duties under Section 9A(5) is only to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**Submissions made by other interested parties**

52. No submissions has been made by any other interested party.

**Examination by the Authority**

53. Annexure 2 to the Rules provides as follows with regard to Causal Link:

*“It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the Designated Authority. The Designated Authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.”*

54. As far as the analysis of injury caused by the other factors is concerned, the Authority notes as under:

**Volume and value of imports not sold at dumping prices:**

55. There are miniscule imports of the subject goods from the subject country in the entire injury period. Further, volume of imports from other countries also is insignificant. Therefore, volume and value of imports and its impact on the domestic industry cannot be analyzed.

**Contraction in demand:**

56. Demand of the product under consideration has not registered any negative growth. Instead, it has increased and shown a positive growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**Changes in the patterns of consumption:**

57. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

**Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:**

58. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**Developments in technology:**

59. Technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in the coming future. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

**Export performance:**

60. The petitioning companies export the product under consideration. However, only information relating to domestic sales has been taken into consideration for assessment of injury.

**C. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY**

61. Despite the submission of the domestic industry with regard to non-requirement of examination of causal link of fresh in case of sunset review investigation, the authority proceeds to examine the causal link. The authority notes that the profits, returns on investment, production and sales have shown improvement during the injury period and accordingly there is no material injury to the domestic industry.

## J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION/RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

### Submissions made by the domestic industry

62. The following submissions have been made by the domestic industry regarding likelihood of continuation/recurrence of dumping and likelihood of continuation/recurrence of injury:

(i) Domestic Industry submitted that no exports from China proves that the Chinese exports cannot compete with the Indian producers unless they indulge in dumping activities. However, it may be added that there is every likelihood of huge potential imports if the duties are not extended seeing the unutilized capacity.

(ii) The present duty is to be continued to protect the interest of domestic industry from the adverse effect of likely dumping of the subject goods from the subject country. Since there have been no exports of the subject goods during the Period of Investigation or in the preceding years, the Domestic Industry has submitted that the Authority needs to determine the likely export price to India on the basis of the export prices of the said goods from China to other appropriate third country, including Domestic Industry. Without prejudice, it is submitted by the Domestic Industry that anti-dumping rules and jurisprudence provides enough indication that “appropriateness” is the criterion to be used when it comes to third country prices.

(iii) Domestic Industry has also submitted the likely prices to India based on the FOB export prices of DI pipes from China to representative countries like Vietnam, Sri Lanka and Turkey. It is submitted that these countries are similar to India in their developmental efforts and infrastructural requirements. Since these countries do not have any domestic production of DI Pipes and, therefore, the prices offered to these countries can reasonably be considered to be true and fair reflection of the likely prices to India. Domestic Industry has also calculated dumping margin and injury margin taking into account all export transactions from China to other countries to analyse the price attractiveness to the Indian market. From the overall data, Domestic Industry has tried to establish that if the goods start flowing into India at landed value based on export price to other countries, the Domestic Industry will certainly start suffering losses.

(iv) Domestic Industry has further submitted that more than 70% of the quantities exported from China to other countries are at a price which would have a positive injury margin and around 83% of the quantities sold to other countries are at dumped prices. This proves beyond an iota of doubt that there is every likelihood that at these prices, if the excess capacity is diverted to India, injury to Domestic Industry is imminent.

(v) Domestic Industry also submitted that none of the Chinese producers / exporters or even the Government of China has bothered to contradict the detailed information and evidence provided by the Domestic Industry. This non-participation only proves that the information provided by the Domestic Industry is incontrovertible and the Authority is obliged to use information provided by Domestic Industry in terms of Rule 6(8).

(vi) Domestic Industry has culled out the information from websites of respective companies and information available from website in relation to the capacities available in China. As per the submissions of the Domestic Industry, excess capacity in China is more than the entire domestic demand in India. The capacities of the subject goods in China is more than 3 times of the capacity of the Domestic Industry. Moreover, the, Chinese capacity of the subject goods is 4.6 times and 4.2 times of the demand in India and production of the Domestic Industry, respectively. The details of which are given below:

Sl. No.	Plant	Capacity
1	Xing Xing Pipe Co. (4 Plants)	1800000
2	Benxi Beitai Pipe Co.	600000
3	Longkhau Fanlin Pipe Co.	250000
4	Saint Gobain(xuzhou) Pipe Casting Co., Ltd.	1700000
5	Dalian Kunda Pipe Co. (2)	200000
6	Jincheng Chunchen Pipe Co.	180000
7	Sun Pipe Co.	150000
8	Xuzhou Everbright (SGPAM)	200000
9	Shandong Jinan Pipe Co.	300000
10	Henan Auyang Pipe Co.	300000



Sl. No.	Plant	Capacity
11	Shanxi Shengyuan Pipe Co.	100000
12	Rhi Zhon Zhu Pipe Co.	200000
13	Qian'an Shi Jintang Iron Pipes co, Ltd	90000
14	Shanxi Guanghua Cast Pipe	300000
15	Yongtong Ductile Cast Ltd	400000
16	Xinjiang Treasury co Ltd	200000
17	Combined capacity of small plants (15 nos. approx.)	300000
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>72,70,000</b>

(vii) Domestic Industry has further provided the comparison of above capacities in China with capacities, production, sales and demand in India to project the potential danger and the imminent likelihood of dumped imports into the country, in the event of revocation of duties. The same is tabulated below:

Particulars	
Chinese Capacity (MT)	72,70,000
Capacity of Domestic Producers (MT)	22,35,000
Demand in India (MT)	15,76,776
Production of Domestic industry (MT)	17,24,624
Sales of Domestic industry (MT)	15,76,368
Chinese Capacity as a % of Capacity of Domestic Industry (%)	325%
Chinese capacity as a % of demand in India (%)	461%
Chinese capacity as a % of production of domestic industry (%)	422%
Chinese capacity as a % of sales of domestic industry (%)	461%

(viii) Domestic Industry has also submitted that the capacities of the subject goods in China is more than 3 times of the capacity of the Domestic Industry. Further, Chinese capacity of the subject goods is 4.6 times and 4.2 times of the demand in India and production of the Domestic Industry, respectively. They have further submitted that, if such quantities are diverted to India, at the likely prices, injury to the Domestic Industry is imminent.

(ix) Export prices to other countries clearly indicate the likely behaviour of the exporters from China. Further, in case, duties are revoked, in order to win the tender bid, producers / exporters would be selling the subject goods into the Indian market at prices lower than the domestic prices in India. That being the case, the increased level of price undercutting is imminent.

(x) Dumping margin calculated on the basis of the likely export price is in the range of 50%-67%. In such a situation, withdrawal of anti-dumping duties will only adversely impact the Domestic Industry. Revocation of duties will encourage free flow of dumped and non-remunerative imports which will definitely have an adverse impact on the domestic selling price, market share and ultimately on profits of the domestic industry.

(xi) Domestic Industry reiterates that the Chinese products are not competitive unless and until they indulge in dumping practices. Further, the present level of anti-dumping is only about 15% to 18% of CIF value, which is very nominal by any standards. Despite this, no exporter has exported the subject goods, nor did they participate in any of the tenders floated by the customers.

#### **Submissions by Interested Parties**

63. No interested party has made any submission in relation to likelihood of recurrence of dumping or injury.

#### **Examination by the Authority**

64. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the AD Rules, which reads as under:

(vii) *A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:*

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*
- (b) *sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*
- (c) *whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and*
- (d) *Inventories of the article being investigated.*

Accordingly, while considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the AD Rules, the Authority considered, inter alia, the following factors

**1. Present and continued imports**

The Authority notes that during POI, the import of the subject goods is mere 73 metric tonnes. The domestic industry has further submitted themselves that subsequent to POI also, there is no likelihood of any import of subject goods having taken place on account of the nature of the product as no Chinese producer/ exporter is understood to have participated in any contract for supply of ductile iron pipe in India. The Authority accordingly notes that there is thus no question of increase of imports, leave alone significant increase of imports.

**2. Price suppression and Price depression**

The Authority notes that in view of above, there is no question of imports causing depressing or suppressing effect on domestic prices,

**3. Surplus Capacities**

This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market.

In relation to the surplus capacity and the likelihood of its diversion to India in case of revocation of duties, it is noted that mere existence of surplus capacity does not establish the likelihood of diversion of surplus production to India prove the likelihood of imports if anti-dumping duties were to be revoked.

**4. Level of inventories**

The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained in view of lack of sufficient cooperation.

**K. POST DISCLOSURE COMMENTS BY INTERESTED PARTIES**

**Submissions made by the Domestic Industry**

65. Following submissions have been made by the Petitioners:

a) In the absence of imports of the subject goods, the Authority is obliged to consider the likely prices of the imports for carrying out the analysis of likelihood of dumping and injury to the Domestic industry. In the disclosure statement no examination has been carried out regarding likelihood of dumping and injury for which detailed information has been provided in their submissions.

b) The detailed documentary evidence filed by the Domestic Industry remains uncontroverted despite sufficient opportunity being given to all the interested parties which included the Government of China, producers and exporters in China. It is further submitted that in the absence of any submissions / evidence by any of the interested parties, the Authority ought to have accepted the submissions / evidence submitted by the Domestic Industry. Domestic Industry also submitted that besides the interested parties, even the Authority has not cited any evidence in the disclosure

statement which could either negate or even dilute the submissions/ information / evidence submitted by the Domestic Industry.

c) The Authority in para 34 proposed to take into consideration the export price of a product which admittedly is not a like article or which may have abnormal prices. This would be in complete contradiction to the provisions of Annexure I to the Anti-Dumping Rules and Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement. It is further submitted by the Domestic Industry that calculation of export price and subsequent dumping margin has no relevance, as it is not for the subject goods and therefore the Authority should not base its conclusion on information which is not for the like article to subject goods.

d) The Authority has also not considered the submissions of the Domestic Industry regarding likely dumping margin based on the actual export data from China to other countries. The legal obligation of the Authority is to examine the likelihood of dumping in sunset review investigations and the Authority is requested to kindly take into consideration in the final findings the detailed information filed by them.

e) When the Authority has itself concluded that there are no imports of like article during the entire injury investigation period, then no meaningful injury analysis can be made. The Authority is requested to avoid making any conclusion based on the current injury information as the same has no logical or legal relevance.

f) That the contention of the Domestic Industry has been completely misunderstood regarding likelihood of imports in India. Domestic Industry has submitted that nowhere they have stated that there is no likelihood of imports from China. The domestic Industry reiterated that no imports are likely if the imports have to bear the burden of the current anti-dumping duties. It is further submitted that the current anti-dumping duties are effective in restoring fair market prices in the country and the imports are bound to recur at dumped prices if the protection of current anti-dumping duties is not continued. Domestic Industry also requested the Authority to kindly delete / modify the premise mentioned in para 62(1) in its final findings, as it is based on incorrect understanding of Domestic Industry's submissions.

g) That the Authority has admitted the existence of huge surplus capacities in China based on the incontrovertible documentary evidence filed by the Domestic Industry. However, the Authority does not find the evidence filed by the Domestic Industry as a conclusive basis to establish the likelihood of the surplus capacities to find their way into India. Domestic Industry has also highlighted the legal requirement is only to establish the likelihood or preponderance of probability that the surplus goods are likely to come into the country. However, from the disclosure statement, it appears that the test which the Authority proposes to apply is that the Domestic Industry must establish "beyond any doubt" that the surplus capacity would find its way in India. Domestic Industry further submitted that any conclusion based on this incorrect reading of the legal obligation of the Domestic Industry, would lead to misleading and flawed conclusions. That the Domestic Industry can, at best, provide information with regard to surplus capacities in China and the attractiveness of the Indian market. Once these set of facts are reasonably established, the inescapable conclusion would be that there is every "likelihood" of the dumped goods to find their way into India. It is further submitted that the Authority cannot ignore the fact that none of the interested parties has given any information/ evidence, which could even dilute, let alone contradict, the well-supported submissions of the Domestic Industry.

h) That the disclosure statement does not carry out the "likelihood analysis", as envisaged under Section 9A(5) of the Custom Tariff Act read with Rule 23 (1B) of the AD Rules. It is further submitted that the Authority has carried out some analysis in respect of certain factors under the heading "Likelihood", while the said factors relate to "Threat of Material Injury" and not per-se to any likelihood analysis. It is also submitted that the test of threat analysis cannot be equated with that of a likelihood analysis.

i) That in the instant case, the Domestic Industry has given detailed documentary evidence in support of the fact that there is every likelihood of dumping and injury in the event the duties are discontinued. The evidence also remains uncontroverted. In view of the incontrovertible evidence filed by the Domestic Industry and in the absence of any evidence / submission to the contrary, the basic ingredients to reach to the conclusion of likelihood of dumping and injury stand adequately satisfied.

j) The Authority should have carried out likely price analysis based on the likely prices to India in the absence of actual imports of like article during the entire injury investigation period. Domestic Industry has further submitted that their submissions relating to likely price and its impact on Domestic Industry has not been dealt with the Authority in the disclosure statement. The Authority is requested to kindly deal with all its submissions and provide fresh opportunity to comment on the same.

#### **Submissions made by other interested parties**

66. No submission has been made by any other interested party.

**Examination by the Authority**

67. The examination of post-disclosure comments is as under:

- i. As regards the submission that the Authority has not carried out sufficient analysis on likelihood or recurrence of dumping and injury, it is noted that the Authority has carried out detailed analysis in this regard at appropriate places of the present findings.
- ii. The Authority notes that there have been negligible imports of the Product under Consideration during the period of investigation and therefore the price attractiveness analysis for the Indian market based on such miniscule import would be inappropriate.
- iii. The domestic industry has itself submitted that even in post-POI period there is no likelihood of any import of subject goods having taken place on account of (a) anti-dumping duty being in force and (b) the nature of the product, as no Chinese producer/ exporter is understood to have participated in any contract for supply of ductile iron pipe in India. Since the import of PUC has almost stopped during the injury period, the requirement of significant rate of increase of dumped imports into India in terms of Annexure II (vii) (a) of the AD Rule for analysis of likelihood of continuation or recurrence of injury is not met.
- iv. The authority further notes that the very fact that the imports of PUC declined sharply during injury period establishes the fact that the anti-dumping measure applied since 23rd August 2007 has already served its intended purpose and that there is no need for its further continuation.
- v. The Authority further takes note of the fact that there are surplus capacities with the Chinese exporters. However, the Authority reiterates that mere creation of additional capacities cannot be considered as a conclusive evidence of likelihood of dumping or injury. The Domestic Industry has failed to provide any evidence to prove that the additional capacities in China would be diverted to India in case of revocation of anti-dumping duty.

**L. Conclusions and Recommendations**

68. Having examined the contentions of the domestic industry and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that continuation of anti-dumping duty is not warranted and accordingly recommends no further extension of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries.

**M. Further Procedure**

69. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority, W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General